

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठारसीन अधिकारी :- हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

(225 आर.टी.एक्ट)

फल संख्या:-35 / 2017

सी.एम.एस. संख्या:-2017 / 00008

उनवान

1. केसरलाल पुत्र पांचुराम उर्फ पांच्या जाति मीना पेशा काश्त निवासी ग्राम कोडयाई तहसील बीली जिला सवाई माधोपुर राजस्थान। (फौत)
 - 1/1. आत्माराम पुत्र केसरलाल
 - 1/2. गिराज पुत्र केसरलाल
 - 1/3. रघुनाथी पुत्री केसरलाल
 - 1/4. मौसमी पुत्री केसरलालजातियान मीना निवासीयान ग्राम कोडयाई तहसील बीली जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान।

—अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण

बनाम

1. कल्याण प्रसाद पुत्र पांचुराम उर्फ पांच्या जाति मीना पेशा काश्त निवासी कोडयाई तहसील सवाई माधोपुर राजस्थान।
2. सरकार जरिये तहसीलदार महोदय लेण्ड होल्डर तहसील बीली जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।
3. श्रीमान प्रबंधक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीली जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।

—रेस्पोंडेन्ट/प्रार्थी

—रेस्पोंडेन्ट्स/अप्रार्थी संख्या 2 व 3

उपस्थित:-

1. श्री श्याम सुन्दर गुप्ता अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 3 अनुपस्थित
3. पैरोकार सरकार उपस्थित

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर



---:: निर्णय ::---

दिनांक 21.11.2022

ह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड बौली जिला सवाई माधोपुर में दायर जस्व प्रार्थना पत्र संख्या 71/2016 वउनवान कल्याण प्रसाद बनाम केसरलाल वगैरहा में पारित निर्णय दिनांक 19.04.2017 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।

करण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/अप्रार्थी सं० 1 व रेस्पोंडेन्ट सं० 1/प्रार्थी सं० 1 सगे भाई है। विवादग्रस्त भूमि ग्राम कोडयाई में स्थित है जो संवत् 2055 से 2056 की आबन्दी खाता सं० 990 के खसरा नम्बर 1030, 1624, व 1669 है जिनके नये खसरा नम्बरान 3909, 3910, 3922 3926/8877, 5822, 5856 कुल रकबा 3.12 हैक्टेयर है। उक्तसंपूर्ण आराजीयात का मूल खातेदारान किशन लाल व जगदीश पि० श्रीराम नाबालिग लिए संरक्षक हरिराम पुत्र कोरेया मीना जाति मीना निवासी कोडयाई है जो अपीलांट व रेस्पोंडेन्ट सं० 1 द्वारा पिता स्व. पांचूराम की मौजूदगी में कय की गई थी। परन्तु दिनांक 20.04.2017 को रजिस्ट्री केवल अपीलांट/अप्रार्थी सं० 1 के नाम करवा दी गई थी। इसी दौरान डू लाल पुत्र पन्नालाल जाति मीना निवासी कोडयाई ने उक्त संपूर्ण भूमि का नामान्तकरण पने नाम खुलवा लिया जो कि कतई अवैधानिक था जिसको राजस्व मण्डल तक मुकदमा डकर उक्त भूमि को पुनः विक्रेतागण के नाम अमल करवाया गया। दिनांक 03.04.1987 से 06.06.2001 तक उक्त भूमि रिसीवर के कब्जे में रही जिसका कब्जा भी प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं० 1 कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त संपूर्ण आराजीयात अपीलांट/अप्रार्थी सं० 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रेस्पोंडेन्ट सं० 1/प्रार्थी ने मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी की के समक्ष वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वह स्वयं समस्त भूमि में से 1/2 हिस्से का घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से अपीलांट/अप्रार्थी सं० 1 को रेस्पोंडेन्ट सं० 1/प्रार्थी के खातेदारी के हिस्से में किसी प्रकार की दखलन्दाजी एवं न बय करने से बाजव मुमतना रहे। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी बौली द्वारा रेस्पोंडेन्ट सं० 01/प्रार्थी का वाद पत्र स्वीकार कर दिनांक 19.04.17 को निर्णय पारित कि अपीलांट/अप्रार्थी सं० 01 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा अन्यथा अन्य आदेश न आशय के लिए पाबन्द किया जाता है कि वह खसरा नम्बर 5856, 3910,3822, 26/8877 वाके ग्राम कोडयाई को रहन वय व अन्य किसी तरीके से मुन्तकिल नहीं करे। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थी सं० 01 ने अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पत्र की है।

प्राधिकारी
गोपुर

में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी बौली ने दूसरे के नोटिस की विधिवत व समुचित रूप से तामील न होते हुये भी आदेश पारित कर दिया। जबकि विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बर 1030, 1624 व 1629 कुल किता 3 कुल आ 12 बीघा 8 बिस्वा वर्तमान खसरा नम्बर 3909, 3910, 3922, 3926/2877, 5852, 5856 किता 6 कुल रकबा 3.12 है। वाके ग्राम कोडयाई अपीलांट/अप्रार्थी सं० 1 की स्वअर्जित दारी एवमं कब्जे काशत की भूमि है। जिस पर अपीलांट बहैसियत खातेदार काशतकार खोज होकर आज दिन तक काशत करता आया है। प्रार्थी/रेस्पोजेन्ट संख्या 1 कल्याण प्रसाद द्वारा अपने पक्ष में कोई दस्तावेज पेश न करते हुये भी मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी बौली ने विवादित भूमि में खसरा नम्बर 5856, 3910, 3922, 3926/8877 वाके ग्राम कोडयाई पर कल्याणप्रसाद का कब्जा काशत होना मानकर भारी कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी बौली द्वारा आदेश जैर अपील दिनांक 19.04.2017 अपास्त फरमाया जावे एवम् रेस्पोजेन्ट सं० 1/प्रार्थी कल्याण प्रसाद का टी० आई० प्रार्थना पत्र सं० 71/2016 अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोजेन्टगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही बाबत आदेश दिया गया।

अपेक्षित अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया कि अर्जित मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी बौली ने अपीलांट पर नोटिस को विधिवत व समुचित रूप से तामील न होते हुये भी उसे समुचित तामील मानकर एकतरफा आदेश पारित किया है। विवादित आराजीयात अपीलांट की पैतृक संपत्ति न होकर स्वयं द्वारा अर्जित संपत्ति है। जिसमें रेस्पोजेन्ट का कोई हिस्सा नहीं बनता है। रेस्पोजेन्ट ने मातहत अदालत में ऐसा कोई सबूत साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजीयात में 1/2 हिस्सा रेस्पोजेन्ट के स्वामित्व का है। रजिस्टर विक्रय पत्र को किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी के आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रिकॉर्डों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 3909, 3910, 3922, 3926/8877, 5822, 5856 कुल किता 5 कुल रकबा 3.12 हैक्टेयर संवत् 1969-72 वाके ग्राम कोडयाई तहसील बौली में केसरलाल पुत्र पांचूराम जाति मीना साठ देह

अधिकारी
पुर

खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 1030, 1624, व 669 केसरलाल द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 20.08.72 द्वारा किशनलाल, जगदीश पेरारान श्रीराम भीना से कय की है।

जस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णित करने हेतु कब्जा मुख्य आधार होता है। कब्जे से संबंधित कोई भी दरतानेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति का निर्धारण अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी बौली में तमय पदाकारान के साक्ष्यों से हो सकेगा। यद्यपि अपीलांत भूमि के रिकार्डेंड खातेदार है, परन्तु भूमि बाबत घोषणा का वाद अभी सक्षम न्यायालय में लम्बित है। अपीलांत ने यह आपत्ति उठाई है कि वह वादित आराजीयात के उसके हिरसे के अनुसार काबिज है परन्तु रिकार्डेंड खातेदार नहीं है। जस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रयोजन भूमि को किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण से बचाना भी है। हमारा मानना है कि जब परिवार के सदस्यों के बीच घोषणा का वाद लम्बित हो, तथा भूमि का हस्तान्तरण किए जाने का डर हो, तो भूमि हस्तान्तरण नहीं करने बाबत खातेदार के विरुद्ध भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है।

यह तथ्य का सिद्धान्त 2018(1) आर.आर.टी. 156 में भी प्रतिपादित किया गया है—

अस्थाई निषेधाज्ञा—प्रार्थना पत्र खारिज किया—उच्च न्यायालय ने आदेश को अपास्त किया, और तदनुसार आदेश स्वीकार किया—कृषि भूमि का वाद—वाद के निस्तारण तक यथावत् स्थिति में का आदेश युक्तियुक्त है—निर्णित आदेश न्यायोचित है।

युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांत स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार की गयी है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी बौली का निर्णय दिनांक 19.04.2017 अपास्त किया जाता है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी बौली में लम्बित मूल वाद के निस्तारण के लिए रिकार्ड एवं मौके यथास्थिति बनाए रखने बाबत आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली दारिजल में होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 21.11.2022 को सुनाया गया।

(हरि राम भीना)
सहायक अपील प्राधिकारी
सहायक माहोदय